



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2012/श्रावण 25, 1934

No. 187]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2012/SHRAVANA 25, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2012

**विषय:** वियतनाम से सभी प्रकार की रिकार्डेबल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (डीवीडी) के आयात पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) जाँच की शुरुआत।

फा. सं. 15/5/2012

यतः सीमाशुल्क टैरिफ नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "सभी प्रकार के रिकार्डेबल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (डीवीडी) (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में 5 मई, 2009 को पाटनरोधी जाँच शुरु की थी और प्राधिकारी के दिनांक 13 नवम्बर, 2009 के प्रारम्भिक निष्कर्षों के आधार पर मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से डीवीडी-आर के आयातों पर दिनांक 12 अप्रैल, 2010 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2010-सीयूएस के तहत अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। अंतिम निष्कर्ष दिनांक 2 जुलाई, 2010 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किए गए थे और राजस्व विभाग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर 28 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. 98/2010-सीयूएस के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था।

2. मै0 स्टोरेज मीडिया प्रोडक्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड मार्केटर्स वेल्फेयर एसोसिएशन (जिसे एतदपश्चात आवेदक या याचिकाकर्ता के रूप में उल्लेख किया गया है) ने वियतनाम से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की शुरुआत सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसरण में करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया है कि मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान व्याप्त परिस्थितियों में अब अत्यधिक परिवर्तन आ गया है जिससे ऐसी स्थिति

उत्पन्न हो गई है कि जहाँ वियतनाम से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क इस समय व्याप्त पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से काफी कम है।

### विचाराधीन उत्पाद

3. मूल जाँच और वर्तमान समीक्षा आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "सभी प्रकार की रिकॉर्डेबल डिजिटल, वर्सेटाइल डिस्क (डीवीडी) है जिसका वियतनाम से निर्यातकों द्वारा भारत के बाजार में पाटन किया जा रहा है। डीवीडी कई तरह की हो सकती है जैसे डीवीडी-आर, डीवीडी+ आर, डीवीडी-आरडब्ल्यू, मिनि-डीवीडी-आर, मिनी डीवीडी-आरडब्ल्यू। डीवीडी को एक बार या कई बार रिकॉर्ड किया जा सकता है। डीवीडी-आर और डीवीडी + आर डिस्क सिंगल या डबल साइडेड हो सकती हैं। सिंगल साइडेड डिस्क (एसएस) में एक रिकॉर्डिंग साइड और एक डमी साइड होती है जबकि डबल साइडेड (डीएस) डिस्क में दोनों साइड्स रिकॉर्डेबल होती है। डीवीडी-आर, डीवीडी + आर डिस्क की रिकॉर्डेबल साइड कई पतों का एक सैण्डविच जैसा होता है।

- मास्टरिंग: ऑप्टिकल डिस्क के लिए मास्टर निर्माण की प्रक्रिया को समान्यतः "मास्टरिंग" के रूप में उल्लिखित किया जाता है जहाँ फाइनल स्टेप में निकिल या उसके समान धातु के मास्टर अर्थात् "स्टाम्पर" बनाया जाता है। इस स्टॉम्पर का उत्तरवर्ती मोल्डिंग प्रक्रिया में मोल्ड के रूप में प्रयोग करके भारी संख्या में ऑप्टिकल डिस्क की डुप्लीकेटिंग की जाती है।
- मोल्डिंग: सर्वप्रथम शैलो स्पाइरल ग्रूव युक्त एक पालीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट आता है जो डिस्क के आन्तरिक डायमीटर से बाह्य डायमीटर तक फैला होता है।
- डाइ-कोटर: इस खण्ड में ब्लैंक सबस्ट्रेट पर एक आर्गनिक डाई रिकॉर्डिंग लेयर (एजेडओ) लगाया जाता है। यह परत रिकॉर्डिंग परत के रूप में कार्य करती है। इस डाई का प्रयोग करके स्पिन कोटिंग तथा डीसी स्पटरिंग के जरिए धातु की परतें लगाई जाती है।
- स्पटर (मेटलाइजिंग) : डिस्क (सिल्वर) पर एक मेटल रिफ्लेक्टिव लेयर लगाई जाती है।
- वाण्डिंग: तब एक एडहेसिव दो रिकॉर्डिंग साइड्स (डबल साइडेड के लिए) या एक रिकॉर्डिंग तथा एक डमी साइड (सिंगल साइडेड के लिए) को अंतिम डिस्क के रूप में जोड़ा जाता है। कुछ सिंगल साइडेड डिस्क को सजावट सहित डमी साइड के रूप में या अतिरिक्त लेयर के रूप में बनाया जाता है जो सतह को इंकजेट, थर्मल ट्रान्सफर या रिट्रान्सफर प्रिन्टर्स द्वारा लेबलिंग के उपयुक्त बनाता है। इस हाट मेल्ट, यूवी कैटियानिक या मुक्त रेडकल प्रक्रिया द्वारा वाण्डिंग की जाती है।
- प्रिन्टिंग: तब स्क्रीन प्रिन्टिंग तरीके से अपेक्षित प्रिन्टिंग डिजाइन की जाती है।
- डीवीडी-आरडब्ल्यू एवं डीवीडी + आरडब्ल्यू बनाना: (डीवीडी-आरडब्ल्यू, डीवीडी + आरडब्ल्यू) को सूचना को न केवल लिखे जाने बल्कि बार-बार लिखे जाने के योग्य बनाने के लिए प्रक्रिया डीवीडी-आर एवं डीवीडी + आर (रिकॉर्डेबल) की निर्माण प्रक्रिया से काफी जटिल है। रिकॉर्डेबल डिस्क की तरह ही, रि-राइटेबल डिस्क भी सिंगल या डबल साइडेड हो सकती है। रि-राइटेबल डिस्क की रिकॉर्डिंग साइड विविध परतों का प्रयोग भी करती है जिसमें शैलो स्पाइरल ग्रूव युक्त एक पालीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट होता है जो डिस्क के आन्तरिक व्यास से बाह्य व्यास तक फैला होता है।
- इसके बाद आता है डाइ-इलेक्ट्रिक लेयर (जिंग सल्फाइड एवं सिलिकॉन डाइ आक्साइड), तदुपरांत एक फेज चेंज अलाय रिकॉर्डिंग लेयर (इण्डियन, सिल्वर, टैलुरियम और एण्टिमनी

या जर्मेनियम, टैलुरियम एण्ड एण्टीगनी), एक अन्य डाइ-इलेक्ट्रिक लेयर एवं मेटल रिफ्लेक्टिंग लेयर (सिल्वर, सिल्वर अलाय, एल्युमिनियम) । डाइ-इलेक्ट्रिक लेयर्स के ऊपर या नीचे अतिरिक्त लेयर्स (जर्मेनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकन डाइ-आक्साइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, जिंग सल्फाइड, एण्टीमनी टेलुराइड एवं अन्य) लगाए जा सकते हैं ।

- डमी साइड पर अतिरिक्त मेटल लेयर युक्त एक फ्लैट पालीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट होता है । तब एक एडहेसिव इनसाइड्स को एक सिंगल डिस्क के रूप में जोड़ता है ।

4. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-85 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्षक संख्या 85232920, 85232950, 85232970, 85234040, 85234050, 85234060, 85234080, 8523409, 85238090, 85235290, 85238050, 85239010, 85239040, 85239050 और 85239090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह इस जाँच के दायरे में किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है ।

### समीक्षा के लिए आधार

5. आवेदक ने मध्यावधि समीक्षा करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आधार सूचीबद्ध किए हैं :-

- (क) पालीकार्बोनेट की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य बढ़ गया है ।
- (ख) वियतनाम की निर्यात कीमत कम हो गई है ।
- (ग) पिछली जाँच के पश्चात डम्पिंग मार्जिन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है ।
- (घ) वियतनाम से आयातों के संबंध में क्षति मार्जिन मूलजाँच की जाँचावधि से बहुत अधिक बढ़ गया है ।

प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दर्ज कराई गई जानकारी के अनुरूप उक्त तथ्यों की जाँच की है ।

### जाँच शुरुआत

6. नियम 23 में निम्नलिखित उल्लेख है :-

"(1) इस अधिनियम की धारा 9क के उपबंधों के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, उस समय तक और उस सीमा तक लागू रहेगा, जो क्षति कारित करने वाले पाटन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो ।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी, आवश्यकता पड़ने पर अपनी ओर से या किसी हितबद्ध पक्षकार की ओर से जो इस समीक्षा की जरूरत के पक्ष में सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर और निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण से पर्याप्त समय बीत जाने पर, पाटनरोधी शुल्क के निरंतर अधिरोपण की जरूरत की समीक्षा करेंगे और इस पुनरीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने से या उसमें कमी बेशी करने से घरेलू उद्योग

को होने वाली क्षति बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है तो केन्द्र सरकार से इसे वापस लेने की संस्तुति करेंगे।

(1ख) उप-नियम (1) या (1क) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क इसके अधिरोपण की तारीख से पाँच वर्षों के अनधिक समय के लिए प्रभावी होगा जब तक की निर्दिष्ट प्राधिकारी, उस अवधि से पूर्व स्वयं अपनी ओर से या उस अवधि के समाप्त होने से पहले एक न्यायोचित समयावधि के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत तर्कसंगत अनुरोध से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से पाटन के बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा, उस समीक्षा की शुरुआत की तारीख से बारह महीना से अनधिक अवधि के अंतर्गत पूरी कर ली जाएगी।

3. समीक्षा के मामले में नियम के उपबंध 6,7,8,9/10, 11,16,17,18,19 और 20 आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू रहेंगे।

7. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बने पाटनरोधी नियम अपेक्षा करते हैं कि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करेंगे। इस मामले में आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी शुल्क नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है और अनुरोध किया है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि करने के लिए एक समीक्षा जाँच की शुरुआत की जाए। प्राधिकारी के पास उक्त आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर और आवेदन की जाँच करने पर प्राधिकारी का विचार है कि वियतनाम के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के उपबंधों के अंतर्गत करना उपयुक्त होगा।

### शामिल देश

8. वर्तमान जाँच में शामिल देश वियतनाम है।

### जाँच अवधि

9. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 अप्रैल, 2011 से 30 मार्च, 2012 (12 माह) है। तथापि क्षति की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े अर्थात् अप्रैल 08-

मार्च 09, अप्रैल 09- मार्च 10 और अप्रैल 10- मार्च 11 और जाँच की अवधि को शामिल किया जाएगा ।

### सूचना प्रस्तुत करना:

10 संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के भारत में स्थित दूतावास के जरिए उनकी सरकार, इस उत्पाद से जुड़े भारत के ज्ञात आयातकों और संबंधित प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा अपने विचारों से अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है ।

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**कमरा सं. 243, उद्योग भवन,**  
**नई दिल्ली-110011**

11. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं ।

### समय सीमा:

12. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जाना चाहिए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

13. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा नहीं जारी रखने की आवश्यकता के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ इस जाँच के शुरू होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर प्रस्तुत करें ।

### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना:

14. प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक सूची पृष्ठ सं. इत्यादि सहित) तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक

3048 9/12-2

सूची पृष्ठ सं. इत्यादि सहित) । प्रस्तुत की गई प्रत्येक सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिह्नित होना अनिवार्य है ।

15. किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को आगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति देने का अधिकार होगा । गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की दो-दो प्रतियाँ अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

16. जिस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया हो; उस सूचना के प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ समुचित कारणों सहित इस आशय का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है तथा/अथवा ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है ।

17. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए या रिक्त छोड़ दिया जाए/संक्षेप में बताया जाए । अगोपनीयता सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके । फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना सार तैयार करना संभव नहीं है, कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए ।

18. प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच पर गोपनीयता हेतु निवेदन को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता हेतु निवेदन प्राधिकृत नहीं है अथवा सूचना प्रदाता या तो सूचना सार्वजनिक करने को अनिच्छुक है या सामान्य अथवा संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत कर रहा है, इस तरह की सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं ।

19. किसी सार्थक अगोपनीय रूपान्तर के बिना अथवा गोपनीयता माँग के लिए एक उचित कारण ब्यौरा दिए बिना किसी तरह का निवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट होने की स्थिति में तथा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करते हुए, इस तरह की सूचना प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इसके किसी पार्टी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे ।

#### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

20. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

**असहयोग**

21. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GÉNÉRAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th August, 2012

**Subject: Initiation of Mid-Term Review (MTR) investigation with regard to anti-dumping duties imposed on imports of Recordable Digital Versatile Disc [DVD] of all kinds from Vietnam**

F. No. 15/5/2012.—

1. Whereas having regard to Custom Tariff Rules, the Designated Authority initiated an antidumping investigation on 5th May, 2009 into alleged dumping of "Recordable Digital Versatile Disk (DVD) of all kinds" (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam and provisional antidumping duty was imposed on imports of DVD-R from Malaysia, Thailand and Vietnam vide customs notification no. 48/2010-CUS dated 12th April, 2010 on the basis of the preliminary findings of the Authority dated 13th November 2009. The final findings were notified vide notification dated 2nd July 2010 and the Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods from subject country vide notification no. 98/2010-CUS dated 28th September, 2010.
2. M/s Storage Media Products Manufacturers & Marketers Welfare Association ( herein after also referred to as the applicant or petitioner) has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the Vietnam in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. They have claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation when anti dumping duty on imports of subject goods from Vietnam is lower than the dumping margin and injury margin that is prevailing at present.

**Product under consideration**

3. The Product under Consideration, as in the original investigation and also in the present review application is "Recordable Digital Versatile Disc [DVD] of all kinds" which is being dumped in the Indian market by the exporters from Vietnam. DVD can be of a number of types, such as DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, mini DVD-R, mini DVD-RW. A

DVD can be recorded once or several times. DVD-R and DVD+R discs can be either single or double-sided. A single-sided (SS) disc is composed of a recording side and a dummy side while a double-sided (DS) disc consists of two recording sides. The recording side of a DVD-R and DVD+R disc is a sandwich of a number of layers.

- **Mastering :** A process of forming a master for optical disks, generally referred to as "mastering", is where a nickel or the like metallic master, i.e., "stamper", is formed at its final step. A large number of optical disks are duplicated with use of the stamper as a mold in a succeeding molding process.
- **Moulding:** First comes a polycarbonate plastic substrate containing a shallow spiral groove extending from the inside to the outside diameter of the disc.
- **Dye Coater:** In this section an organic dye recording layer (AZO) is applied on blank substrate . This layer acts as recording layer. Dye is applied using spin coating and the metal layers by means of DC sputtering.
- **Sputter (Metallizing):** A metal reflective layer is applied on disc (silver).
- **Bonding:** An adhesive then bonds two recording sides (for a double-sided) or a recording and dummy side (for a single-sided) together into the final disc. Some single-sided discs are also topped on the dummy side with decorations or additional layers that provide surfaces suitable for labeling by inkjet, thermal transfer or re-transfer printers. Bonding is done by using a hot melt, UV cationic or free radical process
- **Printing:** Then required printing design is applied by screen printing method.
- **Construction of DVD-RW and DVD+RW:** To allow information to not only be written but also re-written many times over, DVD-RW, DVD+RW) disc construction is more complex than that of DVD-R and DVD+R (recordable). Just like a recordable disc, a rewritable disc can be either single or double-sided. The recording side of a rewritable disc also uses multiple layers beginning with a polycarbonate plastic substrate containing a shallow spiral groove extending from the inside to the outside diameter of the disc.
- Next comes a dielectric layer (zinc sulfide and silicon dioxide), followed by a phase-change alloy recording layer (either indium, silver, tellurium and antimony or germanium, tellurium and antimony), another dielectric layer and a metal reflective layer (silver, silver alloy, aluminum). Additional layers may also be incorporated above or below the dielectric layers (germanium nitride, silicon carbide, silicon dioxide, silicon nitride, zinc sulfide, antimony telluride and others).
- The dummy side consists of a flat polycarbonate plastic substrate sometimes with an additional metal layer. An adhesive then bonds the sides together into a single disc.



4. The product is classified under Chapter 85 of the Customs Tariff Act under custom sub-heading no. 85232920, 85232950, 85232970, 85234040, 85234050, 85234060; 85234080, 8523409, 85238090, 85235290, 85238050, 85239010, 85239040, 85239050 and 85239090. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation

#### Grounds for Review:

5. The applicant has, inter-alia, listed following grounds for undertaking the midterm review
- a) Normal value have increased as a result of increase in polycarbonate price
  - b) The export price of Vietnam has declined.
  - c) Dumping margin has increased significantly after the previous investigation.
  - d) The injury margin in respect of imports from Vietnam has increased significantly since the investigation period of original investigations

The Authority has examined the above factors as per the information filed by the applicant.

#### Initiation

6. Rule 23 states as follows:

*"(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.*

*(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.*

*(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."*

*(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.*

30484/12-3

*(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.*

7. The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. In this case, the applicant has filed an application under Section 9 A of the Customs Tariff Act as amended and Rule 23 of Anti dumping rules substantiating the need for Mid-Term Review of the anti-dumping duty earlier imposed on the subject goods originating in or exported from subject country and has requested for initiation of changed circumstances review for enhancement of anti dumping duty. On the basis of information made available by the aforementioned applicant before the Authority and after examining the application, the Authority considers that the Mid Term Review of the anti dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from Vietnam, would be appropriate at this stage under the provisions of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended read with Rule 23 of Anti Dumping Rules.

**Countries involved:**

8. The country involved in the present investigation is **Vietnam**

**Period of Investigation:**

9. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2011 to 30<sup>th</sup> March 2012 (12 months). For the purpose of analyzing trends of injury, the data of previous three years, i.e. Apr'08-Mar'09, Apr'09-Mar'10, Apr'10-Mar'11 and period of investigation will be considered.

**Submission of Information:**

10. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**Government of India  
Ministry of Commerce and Industry  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Department of Commerce  
Room No.243, Udyog Bhawan,  
New Delhi-110107.**

11. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**Time Limit:**

12. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
13. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of information on confidential basis.**

14. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
15. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
16. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
17. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
18. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
19. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the

Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file:**

20. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

21. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority